

## 26 फरवरी को प्रधानमंत्री करेंगे गुरुग्राम रेलवे स्टेशन नवीनीकरण का शिलान्यास : राव इंद्रजीत

वर्तुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे रेलवे की सौगत

295 करोड रुपए होंगे खर्च

दो चरणों में होगा गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन का कार्य

राजेंद्र पार्क की ओर से भी मिलेगी रेलवे स्टेशन के लिए दूसरी एंट्री

सीमेंट यार्ड व मारुति यार्ड होगा शिप्ट

समाचार गेट ब्लूरे

गुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को रेलवे की अनेक परियोजनाओं की सुधारभूमि वर्तुअल माध्यम से करेंगे जिसमें गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन के आधिकारिकरण की योजना भी शामिल है जिस पर कीरीब 295 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। राव पार्क की ओर से भी गुरुग्राम के लोगों को हाले गाले स्टेशन के लिए प्रवेश विकरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को दो एंट्रीयां मिल जाएंगी। अब राजेंद्र पार्क की ओर से भी गुरुग्राम के लोगों को हाले गाले स्टेशन के लिए प्रवेश विकरित की जाएगी। योजना तैयार की जा रही है कि दौलताबाद-फताई-ओवर से गुरजने वाले वाहन भी सीधे स्टेशन से जुड़ जाएं इसके लिए रेलवे अधिकारियों की जीएमडीए से वार्ता चल रही है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम स्टेशन के अपग्रेडेशन



295 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे और दूसरे चरण में भी कीरीब इतनी ही राशि खर्च की जाएगी। अपग्रेडेशन कार्य में खास बात यह होगी कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को दो एंट्रीयां मिल जाएंगी। अब राजेंद्र पार्क की ओर से भी गुरुग्राम के लोगों को हाले गाले स्टेशन के लिए प्रवेश विकरित की जाएगी। योजना तैयार की जा रही है कि दौलताबाद-फताई-ओवर से गुरजने वाले वाहन भी सीधे स्टेशन से जुड़ जाएं इसके लिए रेलवे अधिकारियों की जीएमडीए से वार्ता चल रही है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम स्टेशन के अपग्रेडेशन

योजना को तैयार कर रहा है। हटेगा सीमेंट यार्ड व मारुति का बाहन यार्ड नए अपग्रेडेशन प्लान के अनुसार रेलवे स्टेशन के आसपास कॉलोनी में रहने वाले लोगों की पुरानी मारुति यार्ड को हटाने की पूरी हो जाएगी। राव ने बताया कि उन्हें कई बार आसपास की कॉलोनी के लोगों को रेलवे स्टेशन के लिए प्रवेश विकरित की जाएगी। योजना तैयार की जा रही है कि दौलताबाद-फताई-ओवर से गुरजने वाले वाहन भी सीधे स्टेशन से जुड़ जाएं इसके लिए रेलवे अधिकारियों की जीएमडीए से वार्ता चल रही है। राव ने बताया कि अपग्रेडेशन प्लान में उन्होंने रेलवे अधिकारियों को जारी किया गया है। पंजाब और राजस्थान सभी लोगों को रेलवे स्टेशन के लिए प्रवेश विकरित की जाएगी। योजना तैयार की जा रही है कि दौलताबाद-फताई-ओवर से गुरजने वाले वाहन भी सीधे स्टेशन से जुड़ जाएं इसके लिए रेलवे अधिकारियों की जीएमडीए से वार्ता चल रही है। राव ने बताया कि अपग्रेडेशन को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए थे जिसे अपग्रेडेशन प्लान में शामिल कर लिया गया है।

राव ने बताया कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन योजना के तहत कीरीब 12 लिफ्ट, एक्सीलेटर्स, दो मैंजिल प्लॉट कोर्ट, प्लॉट और ब्रिज, मटीलेवल पार्किंग, सोलर पैनल आदि लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये नवीनीकरण प्रवात हैं थी सीमेंट यार्ड होने के बारे उनके घरों में सीमेंट की धूल व सांस लेने में काफी दिक्कत का का सामना करना पड़ता है। राव ने बताया कि अपग्रेडेशन प्लान में उन्होंने रेलवे अधिकारियों की जीएमडीए से वार्ता चल रही है।

**प्रभु सिया राम के नाम से भाजपा को परेशानी : विधायक नीरज शर्मा**



नीरज शर्मा का कहना था कि उनके वस्त्र पर जय सिया राम लिखा है और स्वस्तिक विह्न बना है कोई असंसदीय शब्द नहीं लिखा है तो फिर उन्हें क्यों सदन में जाने से रोक जा रहा है

मुझे विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्यों को उठाने की चाहिए। विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष विंदुवार बताएँ कि उसमें विधानसभा अध्यक्ष को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को कहना था कि उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के लिए आचार सहित करने के लिए कहा था साथ ही यह भी पूछा था कि जो चोता मैंने पहन रखा है कृपया विधानसभा अध्यक्ष विंदुवार बताएँ कि उसमें विधानसभा अध्यक्ष को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा ने अपने कपड़ों पर जय सिया राम लिखा है तो फिर उन्हें क्यों सदन में जाने से रोक जा रहा है।

मुझे विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्यों को उठाने की चाहिए। विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष विंदुवार एक में जैसा कि लिखा है कि सदन में किसी तरह का भाजपा सरकार तो चाहती ही है नीरज शर्मा सदन में जाए ताकि इनकी सरकार की ओर बदनामी ना हो।

मुझे विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्यों को उठाने की चाहिए। विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष नीरज शर्मा ने अपने कपड़ों पर प्रधानसभा का नाम एवं स्वास्थ्य का निशान रामायण की चौपाई है। फिर मुझे सदन में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है। भाजपा सियाचाराच के सामान ने नियमों के नियम निम्नलिखित हैं नियम 14 में वर्णित है कि सदन में किसी तरह का बिल्ला धारणा नहीं करेगा नियम 16 में वर्णित है कि सदन में झंडा चिन्ह या प्रदर्शनी नहीं लगाएगा तथा संसदीय पढ़ती और प्रक्रिया के अध्याय 12 में सदनों के आचारण में सभा में रामायण का पकड़ा बिल्ला कर लिया है। विधायक नीरज शर्मा को कहना था कि उनके जनता ने अपने 2 गज का कपड़ा बिल्ला कुछ लिया हूआ पहनकर ही गए। विधायक नीरज शर्मा का कहना था कि मेरी जनता ने किसी भी

साथ ही नीरज शर्मा की विधान सभा एनआईटी 86 की जन समस्याओं की तस्वीरें और उन समस्याओं के बारे में लिखा गया है।

नीरज शर्मा के इस वस्त्र को धारण करने के बाद सरकार ने उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में 26 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने से रोक दिया था साथ ही रामायण की एट हाम पार्टी में भी प्रवेश करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा ने सदन की जारी रामायण की ओर बदनामी नहीं करने की जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा की जीएमडीए को जारी किया गया है।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।

नीरज शर्मा को कहना था कि उनके विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी। ये विधायक नीरज शर्मा को स्वाक्षर करने के बारे में जाएगी।





## संपादकीय

### आरक्षण की उलझी गृह्णी

मराठा आरक्षण के मुद्रे पर विचार करने के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। माना जा रहा है कि सरकार ने इस जटिल मसले को सुलझाने का कोई फॉर्मूला निकाल लिया है, जो बैठक के दौरान प्रस्ताव के रूप में सामने आ सकता है। अपी यदि पाना नहीं है कि इस प्रस्ताव में क्या है? लेकिन इतना तथ्य है कि यह मुद्रा इतना जटिल रूप से तुच्छी है कि कोई एक फॉर्मूला शायद ही इसे सुलझा पाए।

**दलों में सहमती:** दिलचस्प है कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की इस मांग पर महाराष्ट्र के सभी प्रमुख दलों में सर्वसमर्पित काफी पहले से बनी हुई दिख रही है। इसके बावजूद अगर वह मसला सुलझ नहीं पा रहा तो इसके पीछे कानूनी जटिलातों के साथ ही प्रदेश के सामाजिक समीकरणों का भी हाथ है।

**आरक्षण सीमा का सवाल:** राजनीतिक सर्वसमर्पित की ही बढ़ावत महाराष्ट्र विधानसभा 2018 में ही मराठा समुदाय को सकारी नीतियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 16 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर चुकी है। मगर इससे राज्य में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से ऊपर चला गया। नीतीजा यह कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

**निशाने पर समकार:** ख्वाबावक ही इसके बाद मराठा आरक्षण की मांग कर रहे नेताओं और संगठनों ने सरकार को इस असार पर आलोचना शुरू कर दी कि चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य यातायात भीड़ को कम करना और राज्य के दक्षिणी भूभाग परियोजना को उदारता के रूप में सामाजिक विकास करने के कानूनी संरक्षिकेट देकर आरक्षण का हककर बन दिया जाए। जिससे कुल आरक्षण सीमा के अंदर रहते हुए ही उनकी मांग पूरी हो जाए। लेकिन मराठा समुदाय के कथित ऑबीसीकरण की इस कोशिश पर कुण्डी समुदाय नारज हो गया। उसका कहना था कि इससे आरक्षण के उसके हिस्से में कटौती होगी।

**ओबीसी और मराठा:** फिलहाल संरक्षित यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक उड़े राज्य के सरकार प्रभावी मराठा नेता के रूप में ये करने में लगे हैं। उनका मानना है कि मराठा आरक्षण देने के बाद उनका बढ़ेगा। दूसरी ओर सरकार में सामित भट्ठा (अजित भट्ठा) के एक प्रमुख नेता छान भुजबल OBC समुदाय की ओर से इस मसले पर तलवारें ताने हुए हैं। शुरुआती संकेतों के मुाहिबक उड़े OBC समुदाय के तमाम नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है।

**इधर कुआं, उधर खाई:** गैर करने की बात है कि जहां मराठा समुदाय (करीब 30 फीसदी) राजनीतिक तीर पर राज्य का सरकार प्रभावी समूह माना जाता है, वहीं OBC समुदाय संघों के तीर पर सबसे बड़ा समूह (करीब 52 फीसदी) है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य समकार के फॉर्मूले से कौन किनारा संतुष्ट होता है और उससे प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में किस तरह का बदलाव आता है।

## कैफमपी पर लूट के मामले में आरोपी को भेजा जेल



समाचार गेट/रोबिन माथुर

हथीन। समीपवर्ती गांव मिंडकला के निकट कैफमपी पर बड़क सवार चार बदमाशों द्वारा कार सवार लोगों को गन खाईट पर लूटने के मामले में हथीन काइम बांच द्वारा पुलिस मिंट पर लिए गए बदमाश अब्बास निवासी खेडा खलीलपुर के रिमांड अवधि पूरी होने के उपरांत जेल रहते हैं। ये गांव का एक ग्रामीण गांव है जो दूरी से लोगों ने बदल दिया गया है। जाँच अधिकारी एसएसआई उपदेश ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से 500 रुपए भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि लूट के मामले में ये चार आरोपी शामिल थे। जिसमें से एक आरोपी नूर जेल में बंद है। विसंग्रहण वारंवार पर हासिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान लूट में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में भी पता किया गया है। शीशी ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

## होड़ल थाना पुलिस ने वर्ष 2014 के गोकशी एवं जानलेवा हमला मामले में फरार चल रहे आरोपी पर कसा शिकंजा



समाचार गेट/ऋषि भारद्वाज

होड़ल। पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जनकारी के अनुसार एसपी पलबल डॉ अंशु सिंगला के कुशल निरेंशन में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है इसी कड़ी में होड़ल थाना पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। थाना होड़ल प्रभारी निरीक्षक उमर मोहम्मद के अनुसार थाना में धारा 307,427, आईपीसी व 25.54.59 शस्त्र अधिनियम तथा गोकशी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा नं 571/14 में थाना होड़ल में आली में थाना बहोने जिला पलबल निवासी आरोपी को नियम अनुसार गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उपरोक्त मुकदमा में माननीय अदालत से पीओ भी चला आ रहा था। आरोपी के माननीय अदालत से कई बार विज्ञापन व गिरफ्तारी वारंट जारी कराये गये लेकिन आरोपी किसी भी विज्ञापन व वारंट पर माननीय अदालत से हाजिर नहीं हुआ। माननीय अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 ए के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को आज पेश अदालत किया जाएगा।

## संपादकीय/शहर आसपास

# जापान देगा नौ परियोजनाओं के लिए 232 अरब का ऋण

समाचार गेट ब्लॉग/भावना कौशिकी



नई दिल्ली। जापान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में नौ परियोजनाओं के लिए 232.209 अरब जापानी देने की राशि का आधिकारिक विकास सहायता (ओडोरो) ऋण देने की प्रतिबद्धता है। इस ऋण की स्वीकृति आज वित्त मंत्रालय के आधिकारी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री विकास शील और भारत में जापान के राजा जापानी तो रोड शील और भारत में बुनियादी ढांचे का समुचित विकास करना है, जबकि चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य यातायात भीड़ को कम करना और राज्य के दक्षिणी भूभाग परियोजना में कूल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से ऊपर चला गया। नीतीजा यह कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

**निशाने पर समकार:** ख्वाबावक ही इसके बाद मराठा आरक्षण की मांग कर रहे नेताओं और संगठनों के सरकार को इस असार पर आलोचना शुरू कर दी कि चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उदारता भीड़ को जानूनी तो रोड में बुनियादी ढांचे के बाद यातायात भीड़ को कम करना और राज्य के दक्षिणी भूभाग परियोजना में कूल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से ऊपर चला गया। नीतीजा यह कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

**ओडोरो एवं सम्बन्धित घटनाएँ:** दिलचस्प है कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र के सभी प्रमुख दलों में सर्वसमर्पित काफी पहले से बनी हुई दिख रही है। इसके बावजूद अगर वह मसला सुलझ नहीं पा रहा तो इसके पीछे कानूनी जटिलातों के साथ ही प्रदेश के सामाजिक समीकरणों का भी हाथ है।

**आरक्षण सीमा का सवाल:** राजनीतिक सर्वसमर्पित की ही बढ़ावत महाराष्ट्र विधानसभा 2018 में ही मराठा समुदाय को सकारी नीतियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 16 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर चुकी है। मगर इससे राज्य में कूल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से ऊपर चला गया। नीतीजा यह कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

**निशाने पर समकार:** ख्वाबावक ही इसके बाद मराठा आरक्षण की मांग कर रहे नेताओं और संगठनों के सरकार को इस असार पर आलोचना शुरू कर दी कि चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उदारता भीड़ को जानूनी तो रोड में बुनियादी ढांचे के बाद यातायात भीड़ को कम करना और राज्य के दक्षिणी भूभाग परियोजना में कूल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से ऊपर चला गया। नीतीजा यह कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

**ओडोरो एवं सम्बन्धित घटनाएँ:** दिलचस्प है कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र के सभी प्रमुख दलों में सर्वसमर्पित काफी पहले से बनी हुई दिख रही है। इसके बावजूद अगर वह मसला सुलझ नहीं पा रहा तो इसके पीछे कानूनी जटिलातों के साथ ही प्रदेश के सामाजिक समीकरणों का भी हाथ है।

**आरक्षण सीमा का सवाल:** राजनीतिक सर्वसमर्पित की ही बढ़ावत महाराष्ट्र विधानसभा 2018 में ही मराठा समुदाय को सकारी नीतियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 16 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर चुकी है। मगर इससे राज्य में कूल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से ऊपर चला गया। नीतीजा यह कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया।

**ओडोरो एवं सम्बन्धित घटनाएँ:** दिलचस्प है कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र के सभी प्रमुख दलों में सर्वसमर्पित काफी पहले से बनी हुई दिख रही है। इसके बावजूद अगर वह मसला सुलझ नहीं पा रहा तो इसके पीछे कानूनी जटिलातों के साथ ही प्रदेश के सामाजिक समीकरणों का भी हाथ है।

**आरक्षण सीमा का सवाल:** राजनीतिक सर्वसमर्पित की ही बढ़ावत महाराष्ट्र विधानसभा 2018 में ही मराठा समुदाय को सक

# पत्रकार समाज की समस्याओं के समाधान हेतु एमडब्ल्यूबी ने सौंपा कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ज्ञापन

विज ने कहा : सरकार से बात कर निकालेंगे समाधान

समाचार गेट/रोबिन माथुर  
हथीन। हरियाणा के इतिहास में अभी तक बीमी सरकारों ने पत्रकारों को मात्र एक उपयोग का जरिया माना थानि वह वर्ग जिसने हर पीड़ित व्यक्ति-परिवार-समाज और क्षेत्र की आवाज को बुलंद किया, वह वर्ग जिसने कर्मचारियों की समस्याओं को अपना माना, वह वर्ग जो विषय का भी मुख्य बना और सरकारी योजनाओं और नीतियों और समाज के जुड़े कार्यों को जो-जरूर से प्रसारित किया, लेकिन यही वर्ग अपनी लाडाई में हारत रहा। अपने सभी हित इस समाज के दाव पर लग रहे। अन्य वर्ग खुब संपन्न हुए, लेकिन पत्रकार समाज अपने अधिकारों से सदा विचित होता रहा। कोरोना काल के बरिष्ठ पत्रकारों ने अनिल कुमार को किडनी ट्रांसप्लांट व अन्य उपचार के लिए डेंड लाख रुपए, यमुनानगर के पत्रकार रमेश को किडनी ट्रांसप्लांट के बत्त 1 लाख रुपये, पानीपत के दिवंगत पत्रकार देवेन्द्र शर्मा के परिवार को 50000 रुपए, रेवाड़ी के पत्रकार हेषी संगठन पूरी तरह से उस दौरान के नींद्र मुकदर्शक थे। अपने निजी हितों को सदा पत्रकारों के नाम पर साधने वाले पूरी तरह से मान थे। उस संकट की घड़ी में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर धरणी ने वास्तविक रूप से पत्रकार समर्पित एक मजबूत संगठन खड़ा करने का भाव नाया और कुछ वरिष्ठ साथियों से चर्चा-परिचार्कर

तुरंत मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन का पौधा लगा दिया गया (गठन कर दिया गया)। अजय यह पौधा रोपी तरह से जवान विकसित पलटार पेड़ बन चुका है। जिसके मीठे फल पत्रकारों को खूब मिनरल्स दे रहे हैं।

संस्था कोष से पत्रकारों व उनके परिवारों को संस्था कर चुकी है 8 लाख रुपये का वितरण



एमडब्ल्यूबी के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी की अंथक योजनाओं और समाज के जुड़े कार्यों को जो-जरूर से प्रसारित किया, लेकिन यही वर्ग अपनी लाडाई में हारत रहा। अपने सभी हित इस समाज के दाव पर लग रहे। अन्य वर्ग खुब संपन्न हुए, लेकिन पत्रकार समाज अपने अधिकारों से सदा विचित होता रहा। कोरोना काल के बरिष्ठ पत्रकारों ने अनिल कुमार को किडनी ट्रांसप्लांट व अन्य उपचार के लिए डेंड लाख रुपए, यमुनानगर के पत्रकार रमेश को किडनी ट्रांसप्लांट के बत्त 1 लाख रुपये, पानीपत के दिवंगत पत्रकार देवेन्द्र शर्मा के परिवार को 50000 रुपए, रेवाड़ी के पत्रकार हेषी संगठन पूरी तरह से उस दौरान मुकदर्शक थे। अपने निजी हितों को सदा पत्रकारों के नाम पर साधने वाले पूरी तरह से मान थे। उस संकट की घड़ी में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर धरणी ने वास्तविक रूप से पत्रकार समर्पित एक मजबूत संगठन खड़ा करने का भाव नाया और कुछ वरिष्ठ साथियों से चर्चा-परिचार्कर

पत्रकारों के सम्मान को भी बढ़ाने का काम कर रही है। कुछ ही समय पहले राष्ट्रीय राजधानी के बरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र भरतराया के नाम पर अवार्ड शुरू करने की घोषणा भी चंद्रशेखर धरणी द्वारा की गई है।

इसके पहले पत्रकारिता ज्ञान में आयाम स्थापित करने वाले चंद्रीगढ़ के दिवंगत पत्रकार रमेश शर्मा की स्मिति संभिति में शुरू हुआ अवार्ड सीनियर पत्रकार व संपादक यदराम बंसल को दिया गया। जो प्रतिवर्ष हरियाणा के एक पत्रकार को दिया जाएगा। इसके अलावा देवारोहियों से लगातार लोहा लेने वाले देश के अति वरिष्ठ पत्रकार लाला जगत

नायरण के नाम पर भी अवार्ड संस्था द्वारा शुरू किया हुआ है। संस्था 80 वर्ष से ऊपर के एकटॉप पत्रकारों को भी अपने कार्यक्रमों में मुख्य अंतिमियों के हाथों से सम्मानित करवाती रहती है।

एक पत्रिकार में रहे एक से अधिक विधायक या सरकारी कर्मचारी पेंशन ले सकते हैं तो पत्रकार क्यों नहीं? धरणी

मीडिया वेल बींग एसोसिएशन द्वारा हाल ही में दिवंगत पत्रकार ज्ञानेंद्र भरतराया के पुत्र को 10 लाख रुपये के दिवंगत पत्रकार को दी गयी है। जो प्रतिवर्ष हरियाणा के एक पत्रकार को दिया जाएगा। इसके अलावा देवारोहियों से लगातार लोहा लेने वाले देश के अति वरिष्ठ पत्रकार लाला जगत

करवाए गए बीमा की थी। उस दौरान संस्था द्वारा अनिल विज को एक मांग पत्र सौंपा गया और जल्द इन समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन किया गया। दरअसल पत्रकारों को पैंशन देने के मामले में सरकार की अधिकृत्यना 14 नवम्बर 2023 में एक पत्रिकार में एक से अधिक विधायक या सरकारी कर्मचारी पेंशन ले सकते हैं तो पत्रकार क्यों नहीं? धरणी

मीडिया वेल बींग एसोसिएशन द्वारा हाल ही में दिवंगत पत्रकार ज्ञानेंद्र भरतराया के पुत्र को 10 लाख रुपये के दिवंगत पत्रकार को दी गयी है। जो प्रतिवर्ष हरियाणा के एक पत्रकार को दिया जाएगा। इसके अलावा देवारोहियों से लगातार लोहा लेने वाले देश के अति वरिष्ठ पत्रकार लाला जगत

करवाए गए बीमा की थी। उस दौरान संस्था द्वारा अनिल विज को एक मांग पत्र सौंपा गया और जल्द इन समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन किया गया। दरअसल पत्रकारों को पैंशन देने के मामले में सरकार की अधिकृत्यना 14 नवम्बर 2023 में एक पत्रिकार में एक से अधिक विधायक या सरकारी कर्मचारी पेंशन ले सकते हैं तो पत्रकार क्यों नहीं? धरणी

मीडिया वेल बींग एसोसिएशन द्वारा हाल ही में दिवंगत पत्रकार ज्ञानेंद्र भरतराया के पुत्र को 10 लाख रुपये के दिवंगत पत्रकार को दी गयी है। जो प्रतिवर्ष हरियाणा के एक पत्रकार को दिया जाएगा। इसके अलावा देवारोहियों से लगातार लोहा लेने वाले देश के अति वरिष्ठ पत्रकार लाला जगत

पुत्र, भाई-भाई जो विधायक हैं याहं वह ले सकते हैं तो पत्रकारों के एक ही पत्रिकार में रहे पत्रकार सदस्य अलग-अलग क्यों नहीं? इसके साथ-साथ धरणी ने कहा कि अधिकृत्यना में किसी भी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर पैशन या सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने का उल्लेख है। सरकार इसे भी शीघ्र प्राप्त किया गया। विधायकों या जन प्रतिनिधियों के लिए किस प्रकार 2 साल या उससे अधिक समय से अधिक सजावटी रहती है।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि एफआईआर तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हितों के लिए डेंड लाख रुपये के उल्लंघन के लिए बड़ी खाती है।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए।

विधायकों को व्यवस्था पत्रक





